एक नजर में

खेत की आग में झुलसकर वृद्ध किसान की मौत

सतना. जिले के बरौंधा थाना क्षेत्र के बकोटा गांव में अरहर के खेत में लगी आग बुझाने के प्रयास में एक वृद्ध किसान की जलकर मौत हो गई. पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार दोपहर खेत में अचानक आग लग गई, जिसे बुझाने के दौरान 80 वर्षीय मुरलिया यादव आग की चपेट में आ गए. बताया गया है कि आग अचानक विकराल रूप लेती हुई आसपास के खेतों में फैल गई. इसी दौरान मुरलिया आग के बीच फंस गए और बुरी तरह झुलस गए, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

10 दिन में शुरू होगी पीएनजी सप्लाई

एसीएस ने दिए निर्देश

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 8 अप्रैल. अपर मुख्य सचिव खाद्य रश्मि अरूण शमी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिलों के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, नगर निगम एवं नगर पालिका के अधिकारी तथा ऑयल कंपनी एवं सीजीडी के अधिकारियों की बैठक ली.

उन्होंने कहा कि ऐसे हाउसहोल्ड जहां पीएनजी की लाईन कनेक्ट की जा चुकी है, उनको आगामी 10 दिवस के अंदर पीएनजी सप्लाई शुरू करें. ऐसे उपभोक्ताओं को समझाईश भी दी जाये कि यदि उनके द्वारा पीएनजी सप्लाई नहीं ली जाती है, तो भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 3 माह में उनकी एलपीजी सप्लाई बंद की जा सकती है. एसीएस श्रीमती शमी ने गृह विभाग के अधीन आने वाले संस्थाओं/ सुधार गृहों के साथ-साथ पुलिस, सीएपीएफ, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, ऑफिसर्स कॉलोनी, सामान्य प्रशासन पूल के घरों, पुलिस मुख्यालय, पुलिस कॉलोनी, आदि में जहां से आस-पास पाईपलाईन बिछी हुई है, उनको प्राथमिकता के आधार पर पीएनजी कनेक्शन देने के निर्देश दिये. बैठक में बताया गया कि ऐसे क्षेत्र जहां पाईपलाईन बिछी हुई है, उनके रहवासियों एवं व्यवसायियों की सूची तैयार की जाकर कॉलोनियों में कैम्प लगाने की कार्यवाहीं की जा रही है. जिलों को निर्देश दिये गये कि प्रचार-प्रसार एवं कैम्प लगाने की कार्यवाहीं में स्थानीय निकाय नगर निगम एवं नगर पालिका के अधिकारियों तथा वार्ड पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाये. प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में जहां आस-पास पाईपलाईन गई है, उन क्षेत्रों की औद्योगिक इकाईयों की पहचान की जाकर पीएनजी पर शिफ्ट करने के निर्देश दिये गये. सीजीडी संस्थाओं के मैन पावर में वृद्धि करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पॉलीटेक्निक आई.टी.आई. एवं अन्य संस्थाओं से प्रशिक्षार्थियों की सूची प्राप्त कर सीजीडी संस्था को उपलब्ध करायी जा रही है, जो उन्हें लघु प्रशिक्षण देने के बाद कार्य में लगायेंगे.

कालाबाजारी के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई

प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए निरंतर कार्यवाही की जा रही है, अभी तक 3226 स्थानों पर जांच की गई, 3961 एलपीजी सिलेण्डर जब्त किये गए तथा 11 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई. प्रदेश के समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी एवं ऑयल कंपनी के अधिकारियों को सतत रूप से गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पंपों की जांच करने के निर्देश दिये गये है.

रायसेन में बेमौसम बारिश

मौसम का मिजाज अस्थिर

18 जिलों में आंधी-बारिश

भोपाल, 8 अप्रैल. मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. प्रदेश के कई हिस्सों में सक्रिय चक्रवाती सिस्टम के कारण आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है. खासकर ग्वालियर-चंबल और सागर संभाग में इसका असर ज्यादा देखा जा रहा है.

मौसम विभाग के अनुसार, दतिया, निवाड़ी, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, जबकि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर समेत करीब 18 जिलों में अगले 24 घंटों के भीतर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. बुधवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का असर दिखाई दिया. शिवपुरी, दतिया, धार, पीथमपुर और झाबुआ में अच्छी बारिश दर्ज की गई, वहीं रतलाम में धूल भरी आंधी ने लोगों को परेशान किया. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज हवाओं की भी चेतावनी दी है. कुछ क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 40 से 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि अन्य जगहों पर 30 से 40 किमी प्रति घंटा की गति रहने का अनुमान है. यह बदलाव विशेष रूप से दोपहर बाद अधिक प्रभावी रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक 11 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे प्रदेश में मौसम का यह अस्थिर पैटर्न जारी रह सकता है. इससे आगे भी बारिश, आंधी और तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आमतौर पर अप्रैल-मई में तेज गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार बार-बार सक्रिय हो रहे मौसम तंत्र के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

बदलते मौसम का असर कृषि पर भी पड़ रहा

इस बदलते मौसम का असर कृषि पर भी पड़ रहा है. हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, पपीता और केला जैसी फसलें प्रभावित हुई हैं. फरवरी और मार्च में भी मौसम कई बार बदला, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा. कुल मिलाकर, अप्रैल की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज अस्थिर बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहने की संभावना है.

वंदे मातरम् पर अमर्यादित व्यवहार के चलते पार्षद सदन से बर्खास्त

नव भारत न्यूज

इंदौर. नगर निगम में कल वंदे मातरम् गीत नहीं गाने और अमर्यादित व्यवहार करने को लेकर आज सभापति मुन्ना लाल यादव ने फोजिया शेख पार्षद को बर्खास्त कर दिया. बर्खास्त पार्षद ने कहा कि इस्लाम वंदे मातरम की अनुमति नहीं देता है. आज उक्त आपत्तिजनक बयान के बाद नई बहस शुरू हो गई है. भाजपा ने मुद्दे को पकड़ कर हंगामा किया और सदन से निष्कासित होने तक कार्रवाई नहीं होने दी. वहीं कांग्रेस ने उक्त मुद्दे पर पार्टी का सरोकार नहीं होने की बात कहते हुए पार्षद के व्यवहार को गलत बताया है.

नगर निगम में कल बजट पेश करने से पहले वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाया गया. उक्त राष्ट्रगीत खत्म होने के बाद पार्षद फौजिया शेख पहुंची. उक्त मुद्दे को लेकर भाजपा ने आज बहस के दौरान पार्षद फौजिया शेख पर कार्रवाई की मांग करने को लेकर खूब हंगामा किया. उनसे माफी मांगने और वंदे मातरम का अपमान करने को लेकर सभापति ने 10 मिनट का समय दिया. इसके बाद फौजिया को सदन से आज की कार्रवाई से बर्खास्त करने का एलान किया. सदन से निष्कासित होने के बाद फिर उन्होंने आज मीडिया के सामने बयान दिया कि इस्लाम वंदे मातरम् की अनुमति नहीं देता है.

किसने क्या कहा...

- कांग्रेस पार्षद फैजिया शेख ने कहा कि हमारे इस्लाम में वंदे मातरम् बोलने पर मनाही है.
- सभापति मुन्ना लाल यादव ने कहा कि वंदे मातरम गीत को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के चलते पार्षद फौजिया शेख को बाहर किया गया.
- महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि जिस देश का अन्न खाते हैं, जिस देश की नदी का पानी पीते हैं, हवा खाते हैं उस देश के प्रति मान सम्मान न हो यह दुर्भाग्य है कि देश में ऐसे लोग रहते हैं, जो ईरान के नेता के मरने पर श्रद्धांजलि देते है. मगर देश की वंदना करने में और भारत माता की जय बोलने में इनका पेट दुखता है.
- नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, पार्षद फौजिया शेख के बयान से सरोकार नहीं रखती है. कांग्रेस की रग रग में वंदे मातरम और राष्ट्रगान है. देश की आजादी में हमारे हजारों क्रांतिकारियों ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाकर अमूल्य योगदान दिया है. पार्षद फौजिया शेख का ऐसा बोलना गलत है.

अब सरकारी सिस्टम चलाएगा निजी यात्री बसें

- उज्जैन से शुरू हुई नई परिवहन क्रांति
- सिंहस्थ की तैयारी तेज, कंपनी हुई गठित
- विकास प्राधिकरण के सीईओ को सौंपी कमान, कलेक्टर-आयुक्त भी डायरेक्टर

यह है कंपनी का ऑफिस जहां बनेंगे चार्जिंग स्टेशन.

पं. प्रमोद व्यास

उज्जैन. सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन संभाग में यात्री परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य सरकार ने नई परिवहन व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत निजी यात्री बसों को सरकारी ढांचे के अंतर्गत संचालित करने की योजना बनाई गई है. इसके लिए मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के गठन के साथ क्षेत्रीय स्तर पर उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई है.

इस नई व्यवस्था के तहत उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) के सीईओ संदीप सोनी को उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है. उन्होंने पदभार संभालते ही परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आईएसएस मनीष सिंह जो कि जनसंपर्क आयुक्त हैं वे इस कंपनी के सचिव हैं. मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध संचालक को अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है.

कलेक्टर और निगम आयुक्त भी शामिल

कंपनी का निदेशक मंडल भी गठित कर दिया गया है, जिसमें उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा को डायरेक्टर बनाया गया है. इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के मुख्य अभियंता को भी बोर्ड में शामिल किया गया है. किसी भी जनप्रतिनिधि को कंपनी में नहीं रखा गया है, पहले उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल उक्त कंपनी के अध्यक्ष थे.

उज्जैन संभाग से शुरूआत-नई व्यवस्था केवल उज्जैन शहर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका संचालन पूरे उज्जैन संभाग-देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, मंदसौर, नीमच और रतलाम तक किया जाएगा. योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और नियमित परिवहन सुविधा मिल सकेगी. पूर्व में मनीष सिंह उज्जैन आकर योजना का खाका तैयार कर चुके हैं.

100 इलेक्ट्रॉनिक बसें भी आएंगी

सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. उज्जैन में 100 इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाने की तैयारी है, जिनका संचालन मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसकी क्षेत्रीय कंपनी उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा. इन बसों से श्रद्धालुओं और यात्रियों को शहर और आसपास के क्षेत्रों में सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा.

डिपो पर बनेगा चार्जिंग स्टेशन-इसी के साथ मक्सी रोड स्थित पुराने बस डिपो को अत्याधुनिक ई-बस डिपो के रूप में विकसित किया जा रहा है जहां चार्जिंग स्टेशन सहित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. पुराने अनुपयोगी बसों के पुर्जे और कबाड़ सामग्री की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि नए परिवहन ढांचे के लिए स्थान और संसाधन तैयार किए जा सकें.

मुख्यमंत्री के गृह नगर से नवाचार -महाकाल की नगरी उज्जैन, जो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का गृह नगर भी है, वहां लंबे समय से व्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को समयबद्ध बस सेवा मिलेगी और बस संचालन में होने वाले विवादों व अव्यवस्थाओं पर भी लगाम लग सकेगी. उज्जैन से नवाचार किए जाने से अधिकारी भी रोमांचित है.

परिवहन का मजबूत नेटवर्क -सरकार का मानना है कि सिंहस्थ-2028 से पहले सड़कों, फ्लाईओवर, ब्रिज और सार्वजनिक परिवहन के मजबूत नेटवर्क के साथ उज्जैन को एक आधुनिक और सुगम धार्मिक पर्यटन शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर यात्रा सुविधा मिल सकेगी.

स्वामी रामभद्राचार्य महाराज से मिले सीएम

भोपाल, 8 अप्रैल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर तुलसी पीठाधीश्वर, पद्म विभूषण, जगद्गुरू रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज से साकेत वाटिका में सौजन्य भेंट की. मुख्यमंत्री ने स्वामी रामभद्राचार्य का शॉल श्रीफल भेंटकर अभिनंदन किया. स्वामीजी ने मुख्यमंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया और आशीर्वाद दिया.

प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर पटवारी चिंतित

64 % छात्र भोपाल के सांदीपनि विद्यालय में फेल

सरकार की प्रमुख योजनाएं अपेक्षित परिणाम देने में रहीं विफल

विशेष संवाददाता

भोपाल, 8 अप्रैल.मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्रमुख योजनाएं जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम देने में विफल रही हैं.

हालिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए पटवारी ने दावा किया कि भोपाल के एक सांदीपनि विद्यालय में 64 प्रतिशत छात्र फेल हो गए. उन्होंने बताया कि कक्षा 9 में पास प्रतिशत मात्र 48 फीसदी और कक्षा 11 में 76 फीसदी रहा, जो सामान्य स्कूलों से भी खराब स्थिति दर्शाता है. पटवारी ने कहा कि सरकार ने पहले मॉडल स्कूल, फिर सीएम राइज और अब सांदीपनि विद्यालय के नाम से स्कूलों का बार-बार नाम बदलने का काम किया, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण पर खर्च करने के बावजूद परिणाम निराशाजनक हैं.

पटवारी ने बुनियादी सुविधाओं की कमी, बड़े पैमाने पर स्कूलों के बंद होने, रिक्त पदों और उच्च शिक्षा संस्थानों में वेतन में देरी जैसे मुद्दों को भी उठाया और सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की.

बैरसिया और बदई के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उच्च फेल प्रतिशत शिक्षा व्यवस्था के गिरते स्तर को दर्शाता है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षकों पर बार-बार पात्रता परीक्षाओं का दबाव डाला जा रहा है, जिससे विशेषकर सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच रहे शिक्षकों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है.

पेज एक का शेष

आज से गेहूं खरीदी शुरू

किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर फैसले लिए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह विचार किसान और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल संवाद के दौरान व्यक्त किए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है. गेहूं की प्रति क्विंटल कीमत को वर्तमान स्तर तक लाना बड़ी चुनौती थी, हम इसे 2700 रूपये प्रति क्विंटल तक ले जाएंगे. किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाना हमारी प्रतिबद्धता है. हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसी उद्देश्य से उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी की बेहतर व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित किये जा रहे हैं, जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम से संपूर्ण व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाएगी. उपार्जन केंद्रों पर पंपलेट और होर्डिंग के द्वारा भी किसानों को व्यवस्था के संबंध में जानकारियां देने के निर्देश दिए गए हैं.

वर्ष 2026 से किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. उपार्जन केन्द्रों पर आने वाले किसानों को उनके कल्याण तथा हित से जुड़ी शासन की योजनाओं से भी अवगत कराया जाए.

हिमंत के बयान के विरोध में किया प्रदर्शन

विशेष संवाददाता

भोपाल, 8 अप्रैल. मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की.

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और असम के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया. महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरह की 'अमर्यादित और अपमानजनक' टिप्पणी न केवल एक वरिष्ठ जननेता की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और सम्मानजनक संवाद की संस्कृति पर भी आघात करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग संकीर्ण और दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, जो अत्यंत निंदनीय है. इस अवसर पर महक राणा, रूपाली शर्मा, गीता जाटव, माया विश्वकर्मा, गंगा बिलाला, निधि शर्मा, सरोज गुजरे, लता देवरे, शोभा चौंहदे और गीता चौहान सहित बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहीं.

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

कार्यालय मुख्य अभियंता (इंदौर क्षेत्र)

माह मार्च-2026 की अवधि में म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर क्षेत्र व्दारा प्रतिदिन विद्युत प्रदाय के औसत घण्टे

मैं, राजेशचन्द्र जैन, मुख्य अभियंता (इंदौर क्षेत्र) इंदौर, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्देश दिनांक 21.03.2005 के पालन में निम्नलिखित जानकारी माह मार्च-2026 के संबंध में सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित करता हूं :-

क्र.	विवरण	प्रतिदिन विद्युत प्रदाय के औसत घण्टे		
		फरवरी-2026	मार्च-2026	मार्च-2025
1.	संभागीय मुख्यालय	23:57:22	23:55:53	23:56:48
2.	जिला मुख्यालय	23:56:34	23:55:01	23:57:16
3.	तहसील मुख्यालय	23:52:32	23:50:40	23:52:12
4.	घरेलू उपभोक्ता	23:44:35	23:42:55	23:41:12
5.	सिंचाई उपभोक्ता	09:52:41	09:47:41	09:53:38

// बिजली की बचत किजिए//

म.प्र. माध्यम/125263/2026 मुख्य अभिंयता (इं.क्षे.)

विभागीय आकड़े ▶ केंद्रीय राशि पाने के लिए प्रदेश के विभागों की जोर-आजमाइश जारी

वित्तीय वर्ष बीता, केंद्र से नहीं मिले 31,434 करोड़

कन्हैया लोधी

भोपाल, 8 अप्रैल. वित्तीय वर्ष 2025-26 को समाप्त हुए अब 8 दिन हो गए हैं. नया वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो गया है. इस बीच केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के लिए बीते वित्तीय वर्ष में योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए जो राशि देना तय किया था, उसमें से बड़ी राशि अब तक नहीं मिली है.

बीते वित्तीय वर्ष में मध्यप्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए 44355 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि मिलना था, लेकिन वित्त विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश को महज 12921 करोड़ 35 लाख रुपए ही मिले हैं. यानी 31434 करोड़ रुपए की बड़ी राशि अब तक नहीं मिली है, इनमें जल जीवन मिशन की राशि भी शामिल है. अब प्रदेश के विभागों ने केंद्र से राशि मिलने के लिए जोर-आजमाईश का दौर शुरू कर दिया है.

वित्त विभाग ने 31 मार्च तक केंद्र से मिलने वाली राशि का जो ब्यौरा दिया है, वह बेहद चौंकाने वाला है, वहीं विभागों के लिए परेशानी का सबब भी है. केंद्र सरकार से महज 29.13 फीसदी राशि ही मिल सकी है. दरअसल केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलकर संचालित किये जाने वाले योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए दोनों ही सरकार राशि का प्रावधान करती है और फिर उनका आवंटन करती है. ऐसे योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रावधानित राशि में से ज्यादातर राशि मध्यप्रदेश सरकार ने तो जारी कर दी है, लेकिन केंद्र से जो हिस्सा मिलना था, वह अब तक नहीं मिला है. नतीजा अब विभागों को इस राशि के लिए इंतजार करने के साथ ही केंद्र के दरवाजे पर बार-बार दस्तक देना पड़ रहा है और याद दिलाना पड़ रहा है कि उन्हें कितनी राशि दिया जाना है?

➡ गृह विभाग को केंद्र सरकार से 61.31 करोड़ रुपए मिलना है, लेकिन अब तक महज 32.81 करोड़ रुपए ही मिल सके हैं. ➡ राजस्व विभाग को डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के लिए 50 करोड़ मिलना था, लेकिन अब तक कोई राशि नहीं मिल सकी है. ➡ ऊर्जा विभाग को आरडीएसएस योजना के तहत केंद्र सरकार से 1736.33 करोड़ रुपए की बड़ी राशि नहीं मिली है. ➡ कृषि विभाग की अलग- अलग योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए केंद्र से 996.34 करोड़ रुपए की राशि मिलना था, लेकिन अब तक महज 39.14 करोड़ रुपए ही मिल सके हैं, बाकी राशि मिलने का इंतजार है. ➡ कमोबेश यही स्थिति लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की है. विभाग को अलग- अलग योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए केंद्र से 5181.25 करोड़ रुपए मिलना था, लेकिन अब तक 1557.45 करोड़ रुपए ही मिले हैं. इनमें आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राशि भी शामिल है. ➡ नगरीय विकास एवं आवास विभाग की एक दर्जन से अधिक योजनाओं के लिए केंद्र से 1954 करोड़ रुपए के मुकाबले महज 25 लाख रुपए की राशि ही मिल सकी है. यानी यहां भी लगभग शून्य जैसे ही हालात बने हुए हैं.

इन विभागों को मिली भरपूर राशि

➡ वन विभाग को केंद्र सरकार से 179.45 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन उसे 434.54 करोड़ रुपए की राशि मिली है. ये राशि गहन वन प्रबंधन के लिए मिली है.

➡ लोक निर्माण विभाग को केंद्रीय सड़क निधि के तहत 1150 करोड़ रुपए मिलना था, उसके मुकाबले अब तक 1080.67 करोड़ रुपए की बड़ी राशि मिल चुकी है.

➡ स्कूल शिक्षा विभाग को 3700 करोड़ रुपए के मुकाबले 3039 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है, इसमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिले 2945 करोड़ की बड़ी राशि भी शामिल है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60